सम्पूर्ण आजादी का दस्तावेज

डाईवर्सिटी

इयर बुक : 2016-17

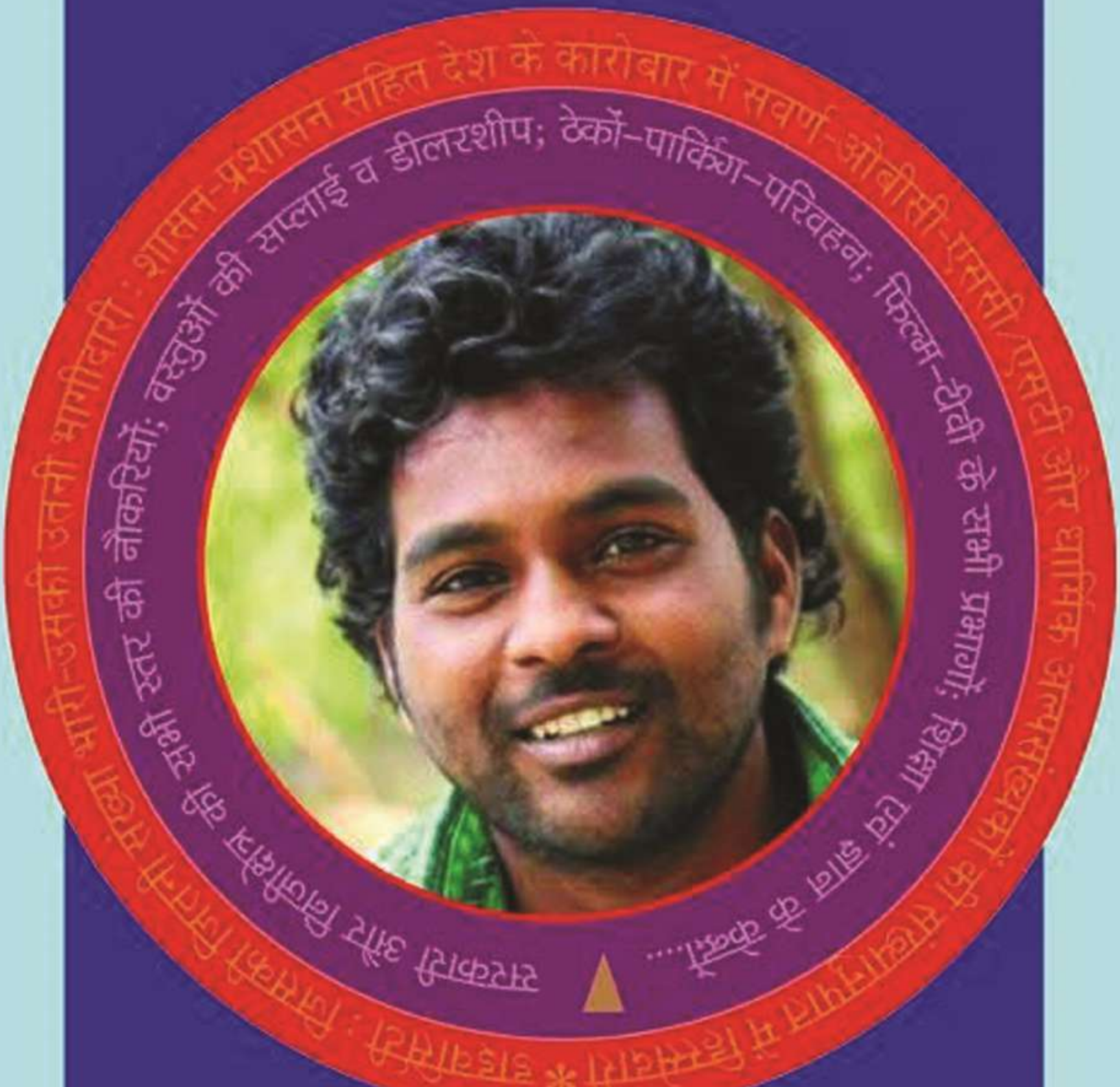

संपादक : एच.एल. दुसाध

सह-संपादक : डॉ. कौलेश्वर-डॉ. कविश कुमार

डाइवर्सिटी इयर-बुक : 2016-17

सम्पादक

एच. एल. दुसाध

सह-सम्पादक

डॉ. कौलेश्वर - डॉ. कविश कुमार

दुसाध प्रकाशन

लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2016

ISBN : 978-81-87618-68-3

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के लिए
द्वारा
प्रकाशक : **दुसाध प्रकाशन**
डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467,
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191

प्रशासनिक कार्यालय
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047,

© पुस्तक का कॉपीराइट संपादक और लेखों का व्यक्तिगत

मूल्य : 2500.00 रुपये

रचना	:	**डाइवर्सिटी इयर-बुक : 2016-17**
संपादक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	राकेश यादव
शब्दांकन	:	कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

डाइवर्सिटी इयर बुक

2016-17 का संपादकीय परिवार

संरक्षक	:	**डॉ. संजय पासवान**
प्रेरणा मण्डल	:	**दिग्विजय सिंह, चन्द्रभान प्रसाद, सुधीन्द्र कुलकर्णी, डॉ. जगदीश प्रसाद, छेदी पासवान, डॉ. एस. एन. संखवार, डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, सुरेश केदारे, डॉ. संजय वठोरे**
मुख्य परामर्शदाता	:	**बुद्ध शरण हंस, दिलीप मंडल**
परामर्श मण्डल	:	**डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, बृजपाल भारती, अभिजीत कुमार, सुदेश तनवर, डॉ. पी. एल. संखवार, डॉ. महेन्द्र प्रताप राणा, शीलबोधि, डॉ. अमरनाथ पासवान**
संपादक	:	**एच.एल. दुसाध**
सह-संपादक	:	**डॉ. कौलेश्वर - डॉ. कविश कुमार**

संपादकीय संपर्क	:	**एच.एल. दुसाध** एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6 नई दिल्ली-110047 मो. 9654816191

समर्पित

गुजरात के ऊना में दलित आंदोलन को
एक नई दिशा देने वाले
संग्रामी साथियों को

संपादकीय

2006 से शुरू हुई डाइवर्सिटी इयर बुक का यह ग्यारहवां अंक है। भारी संतोष का विषय है कि पांच वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद एक बार फिर इसे नियत तिथि, 27 अगस्त को प्रकाशित करने में समर्थ हुए हैं। विविध कारणों से 2012 से ही इसका प्रकाशन नियत तिथि पर नहीं हो रहा था, किन्तु इस बार हो रहा है, इससे डाइवर्सिटी इयर बुक परिवार भारी रहत महसूस कर रहा है। बहरहाल गत एक वर्ष में ढेरों ऐसी घटनाएं हुईं जिससे बहुजन भारत विचलित हुआ किन्तु इनमें सबसे बड़ी घटना, हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली बहुजन छात्र रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या रही, जिसने देश के शैक्षणिक परिसरों में पसरे भेदभाव की समस्या को सतह पर ला दिया।

रोहित वेमुला : इक्कीसवीं सदी का एकलव्य

वैसे तो दुनिया के अन्यान्य देशों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भारत में भी भेदभाव की समस्या व्याप्त है। किन्तु रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद आधुनिक भारत में पहली बार यह प्रश्न बड़ा आकार लेकर उभरा। इससे उठी विरोध की तरंगे विश्वविद्यालयों के कैंपस और महानगरों को पार कर सात समंदर पार तक पहुंच गयीं, जिसका काफी श्रेय सोशल मीडिया को जाता है। सोशल मीडिया में रोहित वेमुला की शहादत पर आईं 'सवर्णवादी शिक्षकों के वर्चस्व के कारण हमारे विश्वविद्यालय बहुजन स्टूडेंट्स के कत्लगाह बन गए हैं', 'यह आत्महत्या नहीं, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता की हत्या है', 'रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गयी है', 'एकलव्य ये देश शर्मिंदा है, द्रोणाचार्य अभी जिन्दा है' इत्यादि जैसी टिप्पणियों ने छात्रों को आक्रोश से भर दिया और देखते ही देखते देश में 21वीं सदी का पहला बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया।

रोहित वेमुला के समर्थन में उतरे लोगों ने शिक्षालयों को जिस सवर्ण-वर्चस्व से मुक्त कराने की आवाज बुलंद की थी, वह सवर्ण वर्चस्व दरअसल ब्राह्मण-वर्चस्व

है। इन्हीं की वजह से शैक्षणिक परिसरों में भेदभाव पसरा है, जिसमें सवर्णों की लिस्ट में शामिल क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्यों इत्यादि की भूमिका सहयोगी मात्र की है। यह ब्राह्मण ही हैं जिनका शिक्षालयों में पूरी तरह दबदबा है। उनका यह दबदबा न सिर्फ भारत, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। कारण, दुनिया के किसी भी देश में ऐसे किसी भी सामाजिक समूह का शिक्षा-तंत्र पर दबदबा नहीं है, जो अपने सिवाय बाकी सामाजिक समूहों के शिक्षा के विरुद्ध अवरोध खड़ा करना धर्म का कार्य समझते हों। जी हां! विश्व में यह एक मात्र ब्राह्मण समुदाय है जो अध्ययन-अध्यापन पर एकाधिकार रखना अपना दैविक-अधिकार (divine-right) समझता है। हिन्दू धर्म-शास्त्रों द्वारा निर्मित सोच ने इसे एक ऐसे मनोरोगी समुदाय के रूप में तब्दील कर दी है जिसमें अपवाद रूप से कुछेक छोड़कर प्रायः सभी में ही छोटा-बड़ा द्रोणाचार्य क्रियाशील हैं। मूलनिवासियों के दुर्भाग्य से भारत के ज्ञात इतिहास में प्रचंड बहुमत से पहली बार एक ऐसी सरकार सत्ता में है, जो देश में भीषणतम रूप में व्याप्त मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या, आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी की पूरी तरह उपेक्षा कर, उस हिन्दू धर्म-संस्कृति के उत्थान में सर्वशक्ति लगा रही है, जिसके जठर से भूरि-भूरि द्रोणाचार्यों का उदय होता रहा है। आज मध्य युगीन सोच की चैंपियन सवर्णवादी सरकार और मॉडर्न द्रोणाचार्यों की युगलबंदी से उच्च शिक्षा में बहुजन छात्रों और गुरुजनों का भविष्य निहायत ही संकटग्रस्त हो गया है।

यही नहीं आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई सरकार बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की पूरी तरह अनदेखी कर मनु के लॉ को रूपायित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब कोई सरकार बहुजनों को उच्च शिक्षा से बाहर करने के साथ संस्कृत, ज्योतिष, पौरोहित्य, योग इत्यादि जैसी प्रगतिविरोधी विद्याओं को थोपने का सबल प्रयास करती दिख रही है। बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने सदियों से शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक-शैक्षिक-धार्मिक-सांस्कृतिक) से जबरन दूर धकेल कर अशक्त बनाये गए लोगों को आरक्षण के जरिये सशक्त बनाने का संविधान में प्रावधान किया था। वैसे तो इस प्रावधान को व्यर्थ करने का प्रयास अतीत की सरकारें भी करती रही हैं, किन्तु वर्तमान सरकार इस मामले में सबको बौना करती प्रतीत हो रही है। ऐसा इसलिए कि इस हिंदुत्ववादी सरकार का एकमेव लक्ष्य हिन्दू ईश्वर के उत्तामांग (मुख, बाहू, जंघा) से जन्मे लोगों का शिक्षा सहित शक्ति के समस्त स्रोतों पर एकाधिकार स्थापित करना है। देश को आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी इसी तबके के हित को ध्यान में रख कर दी गयी है। इन एकाधिक कारणों से बहुजन समाज में सवर्णवादी सत्ता से मुक्ति की

अभूतपूर्व छटपटाहट पैदा हो गयी। अगर बहुजन नेता अकर्मण्यता का शिकार नहीं होते, सवर्णवादी सत्ता अंतिम सांसे गिन रही होती। बहरहाल बहुजन नेतृत्व की निष्क्रियता के चलते अब सवर्णवादी सरकार और द्रोणाचार्यों के मंसूबों पर पानी फेरने की सारी जिम्मेवारी बहुजन छात्र और गुरुजनों पर आन पड़ी है।

इतिहास गवाह है कि विशेष परिस्थितियों पूरी दुनिया में ही छात्र और गुरुजनों ने गौरवशाली इतिहास रचा है। जहां तक भारत का सवाल है 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में छात्रों ने जो भूमिका अदा की उसे कौन भूल सकता है। आजाद भारत में 1974-75 में बहुजन नजरिये से देश की हालत आज जैसी बदतर नहीं थी। बावजूद इसके जेपी के सम्पूर्ण क्रांति के आह्वान पर छात्रों ने जो रोल अदा किया, उससे स्वाधीन भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की सत्ता का पतन हो गया। 74-75 के जेपी आन्दोलन के अल्प अन्तराल के मध्य ही असम के छात्रों ने तो वहां की सत्ता पर कब्जा जमाने तक का कारनामा अंजाम दे डाला। बहरहाल अबतक तो छात्रों ने सिर्फ एक प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमाने का कारनामा अंजाम दिया है लेकिन बहुजन छात्र और गुरुजन यदि दक्षिण अफ्रीका के मूलनिवासी हीरो जैकब जुमा की मानसिकता से पुष्ट होकर विशिष्ट आन्दोलन के लिए वर्तमान में उपलब्ध निश्चित दशाएं तथा सामाजिक असंतोष पनपाने के लिए सापेक्षिक वंचना का सद्व्यवहार करें तो वे विश्व इतिहास में सबसे बड़ी लोकतान्त्रिक क्रांति को अंजाम दे सकते हैं।

अच्छे लोगों में शुमार होने में व्यर्थ : मोदी

राष्ट्र गत एक वर्ष संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की 125वीं जयंती मानाने में व्यस्त रहा। इस दौरान कांग्रेस सहित तमाम दलों ने आंबेडकर की विरासत से खुद को जोड़ने का प्रयास किया, पर इनमें सबसे आगे निकल गयी भाजपा। कोई सोच नहीं सकता था कि 'रिडल्स इन हिन्दुइज्म' के लेखक और वर्षो पहले 'हिन्दू के रूप में न मरने' की घोषणा करने वाले डॉ. आंबेडकर को भाजपा के घोर हिंदुत्ववादी पितृ संगठन 'संघ' की ओर से 'भारतीय पुनरुत्थान के पांचवे चरण के अगुआ' के रूप में आदरांजलि दी जा सकती है, लेकिन यह सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री मोदी के चलते। मोदी के चलते ही आंबेडकर के साथ अपने रिश्ते जोड़ने के लिए भाजपा ने और भी बहुत कुछ किया। मोदी राज में ही इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में मुंबई के दादर स्थित इंदु मिल को आंबेडकर स्मारक बनाने की दलितों की वर्षो पुरानी मांग को स्वीकृति मिली। बात यही तक सीमित नहीं रही, इंदु मिल में स्मारक बनाने के लिए 425 करोड़ का फंड भी मोदी सरकार ने मुहैया करा दिया। लन्दन के जिस तीन मंजिला मकान में बाबासाहेब आंबेडकर ने दो साल रहकर शिक्षा ग्रहण की थी,

उसे गत वर्ष चार मिलियन पाउंड में खरीदने का बड़ा काम मोदी राज में ही हुआ। इनके अतिरिक्त भी आंबेडकर की 125 वीं जयंती वर्ष में भाजपा ने ढेरों ऐसे काम किये जिसके समक्ष आंबेडकर-प्रेम की प्रतियोगिता में बाकी दल बौने बन गए। किन्तु आंबेडकर प्रेम में औरों को पीछे छोड़ने वाली भाजपा सरकार की ओर से आंबेडकर के लोगों के जीवन में सुखद बदलाव लाने लायक एक भी काम नहीं हुआ, इसलिए ही हमने पिछले डाइवर्सिटी इयर बुक की शुरुआत में लिखा था—'भाजपा का दलित प्रेम छलावा है।' किन्तु अपने पहले साल के कार्यकाल के दौरान आंबेडकर के लोगों को बुरी तरह निराश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' घोषित करने के बाद 27 नवम्बर को संसद में दिए गए अपने भाषण में जिन शब्दों में संविधान की बात जन-जन तक पहुचाने की अपील की, उससे बुरी तरह निराश होने के बावजूद उनके आंबेडकर प्रेम को लोगों ने दुबारा गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने कहा था—

'26 नवम्बर इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे उजागर करने के पीछे 26 जनवरी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है, वह 26 नवम्बर में निहित है, यह उजागर करने की आवश्यकता है। भारत जैसा देश, जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, हम सबको बाँधने की ताकत संविधान में निहित है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है और इसीलिए समय की मांग है कि हम संविधान की पवित्रता, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन-जन को परिचित कराने का एक निरंतर प्रयास करें। हमें इस प्रक्रिया को एक पूरे रिलीजियस भाव से, एक पूरे समर्पित भाव से करना चाहिए। बाबा साहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती जब देश मना रहा है तो उसके कारण संसद के साथ जोड़कर इस कार्यक्रम (संविधान दिवस) की रचना हुई है। लेकिन भविष्य में इसको लोकसभा तक सिमित नहीं रखना है। इसको जनसभा तक ले जाना है। इस पर व्यापक रूप से सेमिनार हो, डिबेट हो, कम्पीटीशन हो, हर पीढ़ी के लोग संविधान के विषय में सोचें, समझें और चर्चा करें। इस सम्बन्ध में एक निरंतर मंथन चलते रहना चाहिए और इसीलिए एक छोटे से प्रयास का आरंभ हो रहा है।' यही नहीं, उक्त अवसर पर संविधान निर्माण में डॉ. आंबेडकर की भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला था—'अगर बाबा साहब आंबेडकर ने इस आरक्षण की व्यवस्था को बल नहीं दिया होता, तो कोई बताये कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज की हालत क्या होती? परमात्मा ने उसे वह सब दिया है, जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके कारण उसकी दुर्दशा है। उन्हें अवसर देना हमारा दायित्व बनता है।'

बहरहाल प्रधानमन्त्री ने संविधान में निहित बातों को जन-जन तक पहुचाने

का जो आह्वान किया, उसका राष्ट्र पर कितना असर पड़ा यह तो नहीं बता सकता, किन्तु दावे के साथ कहा जा सकता कि संविधान पर दो दिन की चर्चा को छोड़कर, मोदी सरकार इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, बात सिर्फ मोदी जी के भाषण तक सीमित रह गयी। हां, आपके संगठन बहुजन डाइवर्सिटी मिशन ने उनकी अपील को गंभीरता से लिया और संविधान में निहित बातों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति' जैसी पुस्तक प्रकाशित किया। इस पुस्तक की सम्पूर्ण सामग्री अध्याय दो में संकलित है। इस प्रसंग में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. आंबेडकर के आरक्षण की भूरि-भूरि तारीफ करने के बावजूद शोषित निष्पेषित आंबेडकर के लोगों के हित में उन्होंने इस हथियार के इस्तेमाल में रत्ती भर भी रूचि नहीं ली। आज तो आंबेडकर के लोग मोदी-राज में आरक्षण के खात्मे से बुरी तरह खौफजदा हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी संविधान लागू करने वाले अच्छे लोगों में शुमार होने में व्यर्थ हो चुके हैं। क्यों! इसका जवाब बाबा साहेब की 25 नवम्बर, 1949 वाली ऐतिहासिक चेतावनी में छिपा है। उक्त दिवस को संसद के केन्द्रीय कक्ष से राष्ट्र को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था—'26जनवरी, 1950 को हम राजनीतिक रूप से समान और आर्थिक और सामाजिक रूप से असमान होंगे। जितना शीघ्र हो सके हमें यह भेदभाव और पृथकता दूर कर लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग इस भेदभाव के शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है।'

हमें यह स्वीकारने में कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए कि स्वाधीन भारत के शासकों ने डॉ. आंबेडकर की उस ऐतिहासिक चेतावनी की प्रायः पूरी तरह अनेदखी कर दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में सर्वाधिक आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी, जोकि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है, का साम्राज्य आज भारत में कायम है तथा जिसके कारण भारत का लोकतंत्र विस्फोटित होने की ओर अग्रसर है। भयावह आर्थिक और सामाजिक विषमता के फलस्वरूप लोकतंत्र के विस्फोटित होने की सम्भावना को देखते हुए भी आजाद भारत के शासकों ने इसके खात्मे के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया, आखिर क्यों? इस सवाल का बेहतर जवाब खुद बाबा साहेब आंबेडकर ही दे गए हैं। उन्होंने कहा था, 'संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो , अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा साबित होगा। अगर संविधान बुरा है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा।' जिस बेरहमी से अबतक आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी की समस्या की उपेक्षा हुई है, हमें अब मान लेना चाहिए कि हमारे संविधान का इस्तेमाल करनेवाले लोग अच्छे लोगों में शुमार करने लायक नहीं रहे। इस कसौटी पर मोदी को भी

परखने से स्पष्ट हो जाता है कि वे अच्छे लोगों में शामिल होने में पूरी तरह व्यर्थ हुए हैं। क्योंकि अबतक मोदी जी भीषण आर्थिक और सामाजिक विषमता को लेकर न तो कोई चिंता व्यक्त की है और न इसे कम करने का कोई उपाय। अगर यह समस्या उनके एजेंडे में होती अबतक अवश्य ही कुछ कर चुके होते, पर इसका दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा है इसलिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए देश का एक और प्रधानमंत्री अच्छे लोगों में शुमार होने में चुक हो गया।

सवर्णवादी भाजपा की एकमेव काट : सामाजिक न्याय का मुद्दा

नरेंद्र मोदी के करिश्मे से जिस धूम-धड़ाके के साथ भाजपा 16 मई, 2014 में सत्ता में आई, लगा लम्बे समय तक मोदी की भाजपा अप्रतिरोध्य रहेगी। किन्तु एक साल पूरा होने के पहले ही जिस तरह 10 फरवरी, 2015 में एनजीओ वाली की पार्टी 'आम आदमी पार्टी'ने भाजपा को गहरी शिकस्त दी, लगा भाजपा अप्रतिरोध्य नहीं है। किन्तु दिल्ली में शर्मनाक हार के वावजूद मोदी का करिश्मा अटूट है, ऐसी धारणा राजनीतिक विश्लेषकों में बनी हुई थी। अब उनके करिश्मे की निर्णायक परीक्षा बिहार में होनी थी और जब 8 नवम्बर, 2015 को बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आया, मोदी सरकार की सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों से त्रस्त बहुजनों के चेहरे खिल उठे। बहरहाल बिहार में बुरी तरह हारने के बाद मोदी के करिश्मे को पूरी तरह शून्य होने से बचाने की जिम्मेवारी पांच राज्यों—असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी- में होने वाले विधानसभा चुनावों पर आन पड़ी थी। और 19 मई, 2016 को जब इन राज्यों को चुनाव परिणाम आया, देखा गया मोदी का करिश्मा शून्य पर पहुँचने से बच गया है। पांच राज्यों में मिली मामूली सी विजय को भाजपाध्यक्ष की टीम ने बड़ी विजय के रूप में प्रचारित करते हुए कांग्रेस-मुक्त भारत का नए सिरे से नारा बुलंद कर एक मनोवैज्ञानिक हमला किया जिसमें सत्ता के हाथों बिक चुकी सवर्णवादी मीडिया का भारी सहयोग मिला। भाजपा के दावे में कितना दम है इसे जानने के लिए पढ़े अध्याय 'विविध भारत' में छपा एच.एल. दुसाध का लेख-'कांग्रेस मुक्त भारत का सच।'

पांच राज्यों में येनकेन प्रकारेण मिली छोटी सी सफलता से उत्साहित भाजपा अब यूपी मिशन-2017 में जुट गयी है। वह बिहार की भांति यूपी में विकास के आवरण में हिन्दू-ध्रुवीकरण की तैयारियों में जुट गयी है। उसके मिशन-2017 की चाल को समझने के लिए अध्याय विविध भारत में ही पढ़ें-'विकास और साम्प्रदायिकता की भाजपाई कॉकटेल', 'कैराना वाया कश्मीर' और 'मंत्रीमंडल का नया स्वरुप'। बहरहाल जो लोग भाजपा को यूपी में भी हारते देखना चाहते हैं उनके लिए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से कुछ बातों की ओर ध्यान दिला रहा हूँ। पहला, यह

कि अपनी समस्त गतिविधियां सवर्ण हित पर केन्द्रित रखने के कारण भाजपा आज की तारीख में परम्परागत विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न तबके की आशा और आकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है, इसलिए पूरा का पूरा सवर्णवादी मीडिया के साथ प्रायः सारे सवर्ण बुद्धिजीवि, साधु-संत, उद्योगपति-व्यापारी और लेखक-कलाकार इसके ही साथ हैं।चूंकि यह सिर्फ अल्पजन सुविधाभोगी वर्ग की हितैषी है : शक्ति के स्रोतों से सदियों से बहिष्कृत बहुसंख्य समाज इसकी सोच के दायरे में बिलकुल नहीं है, इसलिए घुमा-फिराकर विशुद्ध राष्ट्र-विरोधी पार्टी है। इस सत्य से यह भी वाकिफ है इसलिए यह अपना राष्ट्र विरोधी चेहरा छुपाने के लिए खुद को अतिरिक्त रूप से राष्ट्रवादी प्रचारित करती है। तीसरा यह लोगों, विशेषकर दिन-हीन बहुजनों में ईश्वर के प्रति व्याप्त दुर्बलता से भलीभांति अवगत है, इसलिए बहुसंख्य लोगों में व्यापत दैविक-गुलामी (divine-slavery) के दोहन के लिए धर्म, देवी-देवताओं के संरक्षक के रूप में अपना एकाधिकार प्रदर्शित करने के लिए सदा सचेष्ट रहती है। अतः यह तय है कि इसकी असल ताकत धर्म और देवी-देवता, उद्योगपति-व्यापारी, मीडिया और मुख्यधारा के बुद्धिजीवी हैं और विकास इसका मुखौटा है। ऐसे में अल्पजनों की इस बेहद ताकतवर पार्टी को सिर्फ सोशल जस्टिस की पीच पर ही खिला कर बोल्ड किया जा सकता है। बाकी विकास और राष्ट्रवाद इत्यादि के मुद्दें पर यह अप्रतिरोध्य है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इसकी दुर्बलता का बेहतरीन इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की भाजपा विरोधी रणनीति राजनीति का एक ऐसा विरल पाठ है, जिसका अनुसरण कर भाजपा को एक नहीं लगातार दस बार शिकस्त दिया जा सकता है। अतः बिहार विधानसभा चुनाव -2015 को सामाजिक न्याय की राजनीति का एक दुर्लभ पाठ मानते हुए बीडीएम की ओर से 'बिहार विधानसभा चुनाव-2015 : मंडल के लोगों ने फोड़ दिया कमंडल' शीर्षक से मेरे संपादन में एक पुस्तक तैयार करायी गयी। भाजपा के खतरनाक मिशन-2017 को देखते हुए इस पुस्तक की सारी सामग्री इयर बुक के तीसरे अध्याय में रखी गयी है। उम्मीद है कि सामाजिक न्यायवादी ताकतें इससे प्रेरणा लेंगी।

सावधान! मोदी सरकार ने एफडीआई के जरिये देश को गुलामी की राह पर ठेल दिया है

पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणामों से उत्साहित मोदी सरकार ने महीने भर के भीतर जो पहला साहसिक कदम उठाया, वह था प्रतिरक्षा क्षेत्र, खुदरा खाद्य व्यापार, नागरिक उड्डयन, केबल नेटवर्क, डीटीएच तथा अन्य टेलिकॉम सेवाओं में 100 प्रतिशत एफडीआई की स्वीकृति। इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदम्भ एक बड़ी उपलब्धि

बताया था। बहरहाल जिसे मोदी सरकार की ओर से उपलब्धि बताया गया, वह देश को आर्थिक गुलामी की और ठेलने वाला एक बलिष्ठ कदम था। इसे जानने के लिए अतीत में जाना होगा। 24 जुलाई, 1991 को जब तत्कालीन ब्राह्मण प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति ग्रहण की, संग-संग संघ की ही आनुषांगिक शाखा, 'स्वदेशी जागरण मंच' के सिरमौर्य दत्तोपंत ठेंगडी अटल-आडवाणी, मोदी-जेटली जैसों को लेकर सड़क पर उतर पड़े। उसके बाद ये लोग देश के गली-कूचों यह सावधान वाणी सुनाना शुरू कर दिए-'अब जो आर्थिक स्थितियां बन या बनायीं जा रहीं हैं, उसके फलस्वरूप देश आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम बन जायेगा। फिर हमें विदेशियों से स्वाधीनता संग्राम की भांति आर्थिक आजादी की एक नयी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।' हालांकि सत्ता में आने के बाद खुद महान स्वदेशी-प्रेमी अटल बिहारी वाजपेयी विदेशियों की आर्थिक रूप से गुलाम बनाने लायक स्थितियों और परिस्थितियों के निर्माण में मुस्तैद हो गए। किन्तु मोदी तो अब सारी हदें तोड़ते नजर आ रहे हैं।अतः बेहतर होगा पाठक आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम बनने के लिए अभी से मानसिक प्रस्तुती ले लें।

दलित उत्पीड़न के प्रतिकार का बलिष्ठतम उपाय : बन्दूकों की दुकानों और लाइसेंस के बंटवारे में डाइवर्सिटी

वैसे तो दलित-उत्पीड़न राष्ट्र के दैनंदिन जीवन का अंग बन चुका है। मार-पीट, गाली-गलौज, हत्या-बलात्कार जैसी दलित उत्पीड़न की सैकड़ों घटनाएँ नियमित रूप से घटित होते रहती हैं। किन्तु इन रूटीन घटनाओं के मध्य ही थोड़े-थोड़े अन्तराल पर कुछ ऐसी घटनाएँ जनसमक्ष आ जाती हैं कि आमतौर पर निर्लिप्त रहने वाला राष्ट्र इस समस्या पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसी ही एक घटना 11 जुलाई को गुजरात के गिर-सोमनाथ जिले के ऊना शहर में घटित हुई, जहां मरी हुई गाय का खाल उतारने के जुर्म में चार दलितों को सरियों और डंडों से बुरी तरह पीटने के बाद कार के पीछे रस्सी से बांध कर घसीटते और पीटते हुए थाने ले जाया गया। विगत दो वर्षों में हिंदुत्ववादी सत्ता के केंद्र में कायम होने के बाद से कई प्रान्तों सहित खुद गुजरात में भी इस किस्म की कई घटनाएं घटीं, किन्तु ऊना की घटना को अंजाम देने वाले गोरक्षकों का दुर्भाग्य यह रहा कि उन्होंने दुसाहस की सारी हदें पार करते हुए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की भांति पूरी घटना का वीडियो बना कर खुद ही वायरल कर दिया ताकि दूसरे गोरक्षकों का हौसला बढ़े। लेकिन सोशल मीडिया में इसके वायरल होते ही राष्ट्र स्तब्ध रह गया और दलित-वंचित समुदाय के लोग गुस्से से फट पड़े।

बहरहाल ऐसी घटनाएँ जनसमक्ष आने के बाद आम तौर पर जो कुछ होता

है, ऊना काण्ड के बाद भी हुआ। नेता घटना स्थल पर पहुंच कर पीड़ितों को ढाढस बढ़ाये; विवेकवान लोगों ने सोशल मीडिया और अखबारों में लेख लिखकर हिन्दू-विवेक को झकझोरा और पीड़ितों ने धरना-प्रदर्शन किया। किन्तु दो बातों के कारण गुजरात के दलितों का विरोध ऐतिहासिक हो गया है। पहला सुरेन्द्र नगर कलेक्टर ऑफिस के सामने मृत मवेशी फेंकना और दूसरा मोरवी जिले के 200 दलितों द्वारा बन्दूक के लिए आवेदन करना। जहां तक सुरेन्द्र नगर कलेक्टर ऑफिस के सामने मरे हुए मवेशी फेंकने का सवाल है, इस घटना ने अभूतपूर्व तरीके से राष्ट्र का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया फेंके गए मृत पशुओं से पट गयी। दलितों ने इसके समर्थन में सारी सीमाएं तोड़ी ही, विवेकवान गैर-दलितों तक का भी इसे भरपूर समर्थन मिला। कुछ दलित बुद्धिजीवियों ने तो सुरेन्द्र नगर अभियान की तुलना अंग्रेज भारत में महात्मा गांधी के उस 'असहयोग आन्दोलन' से कर दी जो कालांतर में भारत की आजादी में मील का पत्थर साबित हुआ। सचमुच गुजरात के दलितों ने सुरेन्द्र नगर अभियान के जरिये दलितों को एक ऐसा अभिनव अहिंसक हथियार सुलभ करा दिया है, जिसका इस्तेमाल कर बर्बर हिन्दुओं का होश ठिकाने लाया जा सकता है।

बहरहाल सुरेन्द्र नगर के असयोग आन्दोलन का धीरे-धीरे सकारात्मक असर होगा, इसके प्रति आशावादी हुआ जा सकता है, किन्तु इससे इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते कि इससे दलित उत्पीड़न घटनाएं रुक जाएँगी। सुरेन्द्र नगर अभियान के बाद भी खुद गुजरात में ही उत्पीड़न की कई घटनाएँ सामने आई हैं। अतः ऐसी घटनाओं से निजात के लिए डॉ.आंबेडकर द्वारा बताये गए उपायों पर अमल करने के लिए आगे बढ़ने का नए सिरे से संकल्प लेना होगा। बाबा साहेब ने बताया है कि मनुष्य समाज में जो तीन बल होते हैं—जनबल-धनबल एवं मनोबल- उससे शून्य होने कारण ही दलितों को हिन्दुओं के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दलित संगठनों और बुद्धिजीवियों की सक्रियता से दलित समुदाय संगठित हो रहा है, जिससे जनबल की समस्या धीरे-धीरे दूर हो रही है। किन्तु धन-बल और मनोबल के मोर्चे पर ठोस कुछ नहीं हो रहा है। यदि दलित समाज के जागरूक लोग इससे चिंतित हैं तो धन-बल के लिए जहां नौकरियों से आगे बढकर सप्लाई, डीलर शिप, ठेकों, फिल्म-टीवी, न्यायपालिका इत्यादि में डाइवर्सिटी लागू करवाने की लड़ाई लड़नी होगी, वहीं मनो-बल से लैस करने के लिए भी बंदूकों के लाइसेंस व दुकानों में डाइवर्सिटी लागू करवाने में सर्व शक्ति लगानी होगी।

और अंत में!

विशेष रूप से आभारी हूं उन पत्र-पत्रिकाओं का जिनमे छपे लेखों से यह वार्षिकी समृद्ध हुई है। आभारी उन तमाम लेखक बंधुओं का हूं जिनके लेखों और साक्षात्कार के बिना इस वार्षिकी को मौजूदा स्वरूप प्रदान करना दुष्कर होता। आभार प्रकट

करता हूं पुस्तक के सह-संपादक डॉ. कौलेश्वर और डॉ. कविश कुमार का, जिन्होंने इस इयर बुक के संपादन में यथेष्ट सहयोग कर मेरा काम काफी हद तक आसान कर दिया। आभार प्रकट करता हूं डॉ. संजय पासवान, बुद्ध शरण हंस, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, दिलीप मंडल, सुरेश केदारे, डॉ. जगदीश प्रसाद, बृजपाल भारती, प्रो. वीरभारत तलवार, डॉ. एसएन और पीएल संखवार, डॉ. प्रदीप चौधरी, शीलबोधी, सुदेश तनवर, डॉ. लाल जी प्रसाद निर्मल, डॉ. राजबहादुर मौर्य, डॉ. पीएल आदर्श, डॉ. राजीव कुमार, निर्मल पासवान, ललन कुमार, योगेन्द्र लाल भारती जैसे समाज परिवर्तनकामी हस्तियों का जिनके सहयोग और उत्साहवर्द्धन से ही डाइवर्सिटी आन्दोलन सफलतापूर्वक दस साल पूरा कर सका। शेष में आभार प्रकट करता हूं अपनी जीवन संगिनी मेवाती दुसाध और बेटे प्रशांत के प्रति जिन्होंने मुझ जैसे निकम्मे व्यक्ति को घर-गृहस्थी की जिम्मेवारियों से मुक्त कर बाबा साहेब के मिशन में कुछ योगदान करने का भरपूर अवसर सुलभ कराया।

जय भीम-जय भारत

27 अगस्त, 2016 **–एच. एल. दुसाध**

ग्यारहवां डाइवर्सिटी डे

अनुक्रम

संपादकीय 5

अध्याय-1

रोहित वेमुला : 21वीं सदी का एकलव्य

अध्याय-1 ए : श्रद्धांजलि

रोहित वेमुला का पत्र... 29

रोहित वेमुला के लिए दो कविताएँ—*डॉ. सुनील कुमार 'सुमन'* 31

आत्महत्या आसान नहीं—*डॉ. श्रद्धा* 33

रोहित तुम जी सकते थे—*भंवर मेघवंशी* 35

रोहित वेमुला की आत्महत्या—*डॉ. सुरजीत कुमार सिंह* 40

रोहित वेमुला : खामोश हो गया एक आंबेडकरवादी—*ब्रज रंजन मणि* 47

सड़कें बोल रही हैं—*पलास बिस्वास* 51

रोहित वेमुला के नाम : एक खत—*बी.एल. यादव* 56

कामरेड रोहित वेमुला चक्रवर्ती की विरासत अमर रहे 57

अध्याय-1 बी : रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर बुद्धिजीवी

अनेक सवालों से घिरी एक मौत—*कुमार नरेन्द्र सिंह* 60

जातिवाद की उत्पादक विचारधारा ब्राह्मणवाद है—*अनिल चमड़िया* 64

रोहित के लिए घड़याली आंसू—*उदित राज* 67

विश्वविद्यालयों में चले एक नया सिलसिला—*सुमित बौद्ध* 71

रोहित वेमुला की मौत : भाजपा के गले का फंदा—*आनंद तेलतुंबड़े* 74

शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव—*प्रो. सुखदेव थोराट* 78

यह दो छात्र समूहों का मामला—*अवधेश कुमार* 82

भेदभाव के बड़े नुकसान—*आकार पटेल* 85

दलित चेतना के आयाम—*अरुण कुमार त्रिपाठी* 88
रोहित की आत्महत्या पर राजनीति भी त्रासदी—*प्रमोद जोशी* 91
गणतंत्र की चुनौतियाँ—*राजेंद्र शर्मा* 94
हिंदुत्व का पुनर्निर्माण भारतीय—*प्रो. बदरी नारायण तिवारी* 97
आंदोलन सुसंगठित करने की जरूरत—*महेंद्र नारायण सिंह यादव* 100
संघर्षों के बीच उम्मीद की किरण—*सत्येन्द्र प्रताप सिंह* 103
रोहित के पक्ष में जातिवादी-अतिवादी-राष्ट्रद्रोही चर्चा—*निखिल आनंद* 108
रोहित वेमुला जैसों की सांस्थानिक हत्या को कैसे देखें?—*डॉ. अनिल कुमार* 119

अध्याय-1 सी : एजुकेशन डाइवर्सिटी

शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव : सवर्ण वर्चस्व का परिणाम—*एच.एल. दुसाध* 125
शिक्षालयों में जरूरी : एजुकेशन डाइवर्सिटी—*एच. एल. दुसाध* 137
उच्च शिक्षा से आरक्षित वर्गों को बाहर करने की साजिश—*एच. एल. दुसाध* 148
उच्च शिक्षा में भेदभाव का सामाजिक मनोविज्ञान—*एच. एल. दुसाध* 153
उच्च शिक्षा में भेदभाव की नियति—*एच. एल. दुसाध* 158
अब तो एजुकेशन डाइवर्सिटी के लिए कमर कस
ही ले : आरक्षित वर्ग—*एच. एल. दुसाध* 162
संस्कृत को बढ़ावा देने की पीछे—*एच. एल. दुसाध* 167
एक नये ढसाल की जरूरत—*एच. एल. दुसाध* 172
शिक्षण जगत में भीषण गैर-बराबरी से निर्लिप्त
बहुजन नेतृत्व—*एच.एल. दुसाध* 177
सारी उम्मीदें अब बहुजन छात्रों पर—*एच. एल. दुसाध* 182

अध्याय-1 डी : साक्षात्कार

साक्षात्कार की प्रश्नावली 206
हरिशंकर शाही 212
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण 215
बुद्ध शरण हंस 221
डॉ॰ अमरनाथ पासवान 233
शीलबोधि 236
डॉ. के.के. प्रियदर्शी 242

अध्याय-2

कैसे हो संविधन के उद्देश्यों की पूर्ति

अध्याय-2 ए : संसद में संविधान दिवस पर चर्चा

हमारा संविधान भारत का राष्ट्र दर्शन ग्रन्थ है–*श्रीमती सुमित्रा महाजन* 247

संविधान ने हमारे लोकतंत्र को अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है–*श्रीमती सोनिया गांधी* 255

संविधान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि : आरक्षण–*श्री मुलायम सिंह यादव* 258

हासिल करना होगा : पॉलिटिकल पावर की 'मास्टर की'–*सुश्री मायावती* 262

सामाजिक विषमता : सारे गुनाहों की जननी–*श्री शरद यादव* 281

दिनोंदिन हमारा प्रजातंत्र नीचे जा रहा है–*श्री राम विलास पासवान* 290

करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा है–*डॉ. सत्यनारायण जटिया* 299

वर्तमान सरकार को धर्मनिरपेक्ष शब्द पसंद नहीं–*श्री तारिक अनवर* 304

बाबा साहेब के सपने अभी अधूरे हैं–*श्री दिलीप कुमार तिर्की* 308

आरक्षण भीख नहीं, संरक्षण की व्यवस्था है–*श्रीमती अनुप्रिया पटेल* 310

सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है–*प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी)* 312

अध्याय-2 बी : संविधान दिवस पर अखबार और बुद्धिजीवी

शीतकालीन सत्र का पहला दिन 329

संविधान दिवस की सार्थकता 331

विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान 333

तंज न तकरार बस सद्भाव 334

त्रासदी से सीख न लेना सबसे बड़ी त्रासदी 335

बीच बहस में 336

संवैधानिक मूल्यों में विश्वास की जरूरत–*सचिन कुमार जैन* 338

संविधान दिवस की सार्थकता–*कृपाशंकर चौबे* 342

सामाजिक क्रांति को भूलने के खतरे–*अरुण कुमार त्रिपाठी* 345

आंबेडकर के नाम पर कोरी श्रद्धांजलि–*प्रकाश करात* 348

संविधान के उद्देश्यों को पाने के लिए : डाइवर्सिटी–*एच.एल. दुसाध* 350

संविधान प्रणेता की चेतावनी–*एच.एल. दुसाध* 353

भारतीय-संविधान बनाम मनुस्मृति–*एच.एल. दुसाध* 357

सामाजिक न्याय का एजेंडा–*एच.एल. दुसाध* 361
गणतंत्र दिवस का सन्देश–*एच.एल. दुसाध* 365
अध्याय-2 सी : साक्षात्कार
साक्षात्कार की प्रश्नावली 370
प्रश्नोत्तर 380
अरविन्द कुमार 380
भगवान स्वरूप कटियार 385
डॉ. रतन लाल 392
हरिशंकर शाही 394
सोबरन कबीर 398
बुद्ध शरण हंस 401
गोपाल राम 428
नुसरत अली 430
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण 433
डॉ. कुसुम मेघवाल 441
वीरचंद्र दास 450
भीम शरण हंस 453
डॉ. महेन्द्र कुमार 458
डॉ. राज बहादुर मौर्य 461
के.पी. राहुल 466
जवाहर लाल कौल 475
महेंद्र नारायण सिंह यादव 482
शीलबोधि 487
मूलचन्द सोनकर 491
माता प्रसाद 514
पी. एल. आदर्श 520
श्यामलाल धनुषधारी 523
संजीव चन्दन 525

अध्याय-3

बिहार विधानसभा चुनाव-2015

अध्याय-3 ए : बिहार में चुनावी जंग

लालू फिर अपने स्टाइल में 529

राजनीतिक दलों के समक्ष बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अपील! 531

चुनावी समर के बीच नारा युद्ध : तुकबंदी नारों से जनता को
रिझाने की कोशिश 538

छोटे दलों के हैं अरमान बड़े–*ब्रजेश कुमार* 539

देश की फिरंगी है भाजपा : लालू 540

मतदाताओं को छल रहे बीजेपी नेता : लालू 541

आरक्षण के मुद्दे पर डर से बीफ को मुद्दा बना रही भाजपा : लालू 542

गोमांस पर लालू को घेरने की संघी चाल–*एच.एल. दुसाध* 543

भागवत बोलें या लालू, बहस तो आगे बढ़ेगी–*प्रमोद जोशी* 544

महागठबंधन को थमाई 'भागवत' पोथी आरएसएस–*प्रेम कुमार मणि* 547

तो क्या बिहार है संघ की नई प्रयोगभूमि!–*चंदन* 550

आखिर क्या मंशा है संघ प्रमुख की?–*उपेन्द्र प्रसाद* 553

नेताजी नीतीश को पटकना क्यों चाहते हैं?–*अमलेंदु उपाध्याय* 555

हिंदुत्व : कोई हाशिया, न कोई मुख्यधारा!–*राजेंद्र शर्मा* 558

भागीदारी नहीं, भीखनुमा वादों के सहारे वोट खरीदेगी भाजपा!–*एच.एल. दुसाध* 561

कैसे मिले संघ के आरक्षण विरोधी षडयंत्र से निजात–*एच.एल. दुसाध* 562

यह जाति बनाम धार्मिक चेतना के राजनीतिकरण का युद्ध है–*एच.एल. दुसाध* 567

हैट्स ऑफ टू मांझी साहब! हम का बेहतरीन घोषणापत्र–*एच.एल. दुसाध* 568

कांशीराम बनाम हेडगेवारवाद की जंग में तब्दील
होता बिहार चुनाव–*एच.एल. दुसाध* 570

मोदी : विविधता के सबसे बड़े दुश्मन–*एच.एल. दुसाध* 574

मोदी और विविधता–*एच.एल. दुसाध* 575

मोदीवादी विकास से सावधान–*एच. एल. दुसाध* 578

अध्याय-3 बी : बिहार का जनादेश

महागठबंधन की महाजीत

बनारस से मोदी के खिलाफ शुरु करेंगे आन्दोलन : लालू 582

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

- ✓ We champion diverse voices and perspectives
- ✓ Your support helps amplify underrepresented authors
- ✓ We provide free access to educational institutions
- ✓ Building bridges through shared stories
- ✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

- Curate diverse book collections
- Support authors from marginalized communities
- Provide free resources to educators
- Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library